



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2006]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2012/आश्विन 17, 1934

No. 2006]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2012/ASVINA 17, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2012

सं. 20 (आरई-2012)/2009-2014

विषय : वर्ष 2012-13 के लिए संगमरमर के खनन में विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों हेतु अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉकों का आयात करने हेतु कोटे के आवंटन के लिए नीति ।

का.आ. 2423(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-I (आयात) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. अध्याय 25 के अंत में आयात लाइसेंसिंग टिप्पणी सं. 5 को जोड़कर इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"5. भारतीय कंपनियाँ जिन्होंने विदेश में खनन में निवेश किया है, के लिए सुविधा।

यह नीचे दी गई शर्तों के अधीन होगा:-

5(क) पात्रता:

- (i) खनन कंपनी जिसमें निवेश किया गया है को भारतीय कंपनी की 100 प्रतिशत अनुषंगी होना चाहिए।
- (ii) 31.3.2012 को न्यूनतम निवेश दस करोड़ रुपये होना चाहिए और जो आज भी लागू है।
- (iii) ऐसा निवेश केवल संयंत्र और मशीनरी में होना चाहिए। लीज आधार पर किसी संयंत्र और मशीनरी पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) विदेशी खनन कंपनी को उत्पादनशील होना चाहिए और अपने नाम पर उत्पादन लाइसेंस होना चाहिए।

(ख) अनुमत की जाने वाली मात्रा:

(i) केवल स्वयं की विदेशी खानों से उत्पन्न संगमरमर ब्लॉकों के आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ii) कुल वार्षिक आयात मात्रा 1 लाख मीट्रिक टन होगी।

(iii) किसी आवेदक को पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष से आशय भारतीय वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल, 2011-31 मार्च, 2012 तक है) में विदेशी खानों से खनन किए गए तथा बेचे गए संगमरमर की कुल मात्रा अथवा 30,000 मीट्रिक टन में से जो भी कम हो, से अधिक की हकदारी नहीं दी जाएगी।

(iv) यदि पात्र आवेदकों द्वारा की जाने वाली आयात की मात्रा 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक होती है तो यथा-अनुपात के आधार पर मात्रा का आबंटन किया जाएगा। यथानुपात आधार पर आबंटन का वितरण विदेशी खानों से पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित मात्रा से प्राप्त की गई सकल बिक्री के आधार पर किया जाएगा। बिक्री की मात्रा एक निष्पक्ष सनदी लेखापाल के द्वारा प्रमाणित की जाएगी और यह विदेशी खानों (भारतीय कंपनी की सहायक) के वार्षिक लेखों के साथ होनी चाहिए।

(ग) आवेदन-पत्रों को दायर किया जाना:

आवेदन-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय(मुख्यालय) में 25 अक्टूबर, 2012 को सांय 5 बजे से पहले पहुँच जाने चाहिए।

(घ) न्यूनतम मूल्य:

ऐसे आयात 325 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (एमटी) के न्यूनतम मूल्य के अधीन होंगे।

(ङ.) आईटीसी एचएस कोड:

ऐसे आयात आईटीसी एचएस कोड संख्या 25151100 और 25151210 के तहत अनुमत होंगे।

(च) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त:

सभी लाइसेंस वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होंगे।

(छ) मासिक विवरणी:

लाइसेंसधारक अपने द्वारा किए गए आयातों के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को लाइसेंस प्राप्त करने के प्रत्येक अगले माह की 15 तारीख को मासिक विवरणी भेजेगा (उदाहरण के लिए यदि एक लाइसेंस 13 सितम्बर को प्राप्त किया जाता है तो लाइसेंस धारक 15 अक्टूबर तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा)। यह अनिवार्य आवश्यकता है।

(ज) आयात लाइसेंसों की वैधता:

संगमरमर के आयात के लिए लाइसेंसों की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 12 महीने तक होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभाव:

संगमरमर खनन में विदेश में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए अपरिष्कृत संगमरमर ब्लॉकों के आयात के लिए 1 लाख मी.टन के वार्षिक कोटे सहित आयात नीति अधिसूचित की गई है।

[फा. सं. 01/53/162/293/संगमरमर/एम-3/एम 13/आयात प्रकोष्ठ]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2012

No. 20 (RE-2012)/2009-2014

Subject : Policy for allocation of quota for import of Rough Marble Blocks for Indian companies investing abroad in marble mining, for the year 2012-13.

S.O. 2423(E).—In exercise of powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 as amended, read with paragraph 2.1 for the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Central Government hereby makes the following amendments in Schedule-I (Imports) to the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items :—

2. Import Licensing Note No. (5) is inserted at the end of Chapter 25, to read as :

“5. Facility for Indian companies who have invested in Mining abroad.

This will be subject to conditions laid down as under:

5(a): Eligibility:

- (i) Mining company where such investment is made must be a 100% subsidiary of the Indian company.
- (ii) Minimum investment should be Rupees 10 crores as on 31.3.2012 and is subsisting.
- (iii) Such investment should only be in plant and machinery. No plant and machinery on leased basis will be considered.
- (iv) The overseas mining company should be operational and have the operating license in its own name.

(b) Quantity to be permitted:

- (i) Only marble blocks produced from its own quarries overseas shall be allowed for import.
- (ii) The total annual import quantity will be limited to 1 lakh MT.
- (iii) The quantity to be allocated for import per applicant shall not exceed 30,000 MT or the total quantity of marble mined and sold from its overseas mines in the previous financial year, whichever is less. (Reference to financial year would be Indian financial year i.e 1st April 2011-31st March 2012)
- (iv) If the quantity to be imported by the eligible applicants exceeds 1 lakh MT, then allocation will be on a pro rata basis. Distribution of pro rata allocation will be on the basis of total sale of quantity produced in the previous financial year from its mines overseas. Quantum of sale shall be certified by an independent Chartered Accountant and will be accompanied with annual accounts of foreign mines (subsidiary of Indian Company).

(c) Filing of Application;

Applications should reach DGFT(HQ) office at Udyog Bhavan, New Delhi before 5 pm on 25th October 2012.

(d) Floor Price;

Such imports shall be subject to a floor price of US\$ 325 per Metric Tonne (MT).

(e) ITC HS Codes;

Such imports shall be permissible under ITC HS Codes 25151100 and 25151210.

(f) Actual User Condition;

All authorisations shall be subject to actual user condition.

(g) Monthly Return;

Authorisation holders shall file monthly returns regarding imports made by them, to the concerned Regional Authority of DGFT by the 15th of each succeeding month in which authorisation is obtained (for example if a authorisation is obtained on 13th September, the authorisation holder will file monthly return by 15th of October and for each month thereafter). This is a mandatory requirement.

(h) Validity of Import authorisation;

Authorisation for Import of marble will have a validity of 12 months from date of issue.

3. Effect of this notification:

Import Policy for allocation of quota for import of Rough Marble Blocks by Indian companies investing abroad in marble mining has been notified with an annual quota of 1 lakh MT.

[F. No. 01/53/162/293/Marble/M-3/AM 13/IC]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade